International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 02(III), April - June, 2023, pp. 17-26

नकदी रहित भारतीय अर्थव्यवस्था एक विश्लेषण (मन्दसौर जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. निशा शर्मा*

प्रस्तावना

विमुद्रीकरण से पूर्व भारत में नकदी आधारित अर्थव्यवस्था का बोलबाला था । किन्तु 8 नवम्बर, 2016 विमुद्रीकरण के पश्चात् भारत में डिजिटल लेन–देन का प्रचलन बढ़ा। विमुद्रीकरण के मुख्य कारणों में एक प्रमुख कारण डिजिटल लेन–देन को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था को नकदीरहित अर्थव्यवस्था (ब्मसमे म्बवदवउल) में बदलना था । हालांकि इस दौरान डिजिटल लेन–देन में निःसंदेह वृद्धि दर्ज की गई, किन्तु इससे नकदी के चलन में कमी आई हो, ऐसा नहीं है । देश की ळक्च में जहां 2016–17 में नकदी का हिस्सा 8.70 प्रतिशत था, वहीं यह वर्ष 2022–23 में बढ़कर 12.4 प्रतिशत हो गया ।[1] मैकिन्स ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार भारत में वाल्यूम के हिसाब से लगभग 89 प्रतिशत लेन–देन नकदी में होता है । भारत में रिटेल प्लेटफार्म पर 65 प्रतिशत कारोबार कैश ऑन डिलिवरी (COD) से होता है ।[2] अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि– भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकदी की बादशाहत आज भी कायम है ।

नकदीरहित अर्थव्यवस्था

जब किसी अर्थव्यवस्था में नकदी (नोट एवं सिक्कों) का प्रवाह ना के बराबर हो जाए तथा सभी लेन–देन डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service- INPS-NEFT), राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक फंड्स ट्रांसफर (National Electronic Fund Transfer- NEFT) और रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (Real Time Gross Settkement- RTGS) जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों एवं एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payment Interface) जैसे भुगतान माध्यमों से होने लगे, तो यह स्थिति नगदीरहित (Cashless) अर्थव्यवस्था के रूप को बताती है ।

नकदीरहित अर्थव्यवस्था के लाभ

- **टैक्स चोरी पर रोक :–** यदि अर्थव्यवस्था कैशलेस होती है, तो टैक्स चोरी की घटनाओं में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी । ऐसा इसलिये क्योंकि प्रत्येक कैशलेस लेन–देन के प्रमाण डेटाबेस में अंकित हो जाते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की वास्तविक आय से संबंधित आंकड़े जुटाने में आसानी होती है ।
- **काले धन पर रोक :–** कैशलेस समाज का एक मुख्य **लाभ** यह है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिये किये गए आर्थिक लेन–देन ब्लैक मनी के बाजार को खत्म कर सकता है । नकदी आधारित अर्थव्यवस्था में ब्लैकमनी इकट्ठा करना, नशीली देवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद, जबरन वसूली आदि जैसे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना आसान बन जाता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था इन से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगी ।
- **बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुंच :–** यह प्रयास सभी को बैंकिंग सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने में अत्यन्त ही सहायक होगा । ऐसा इसलिये, क्योंकि इस व्यवस्था में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु बुनियादी ढ़ांचा खड़ा करने के बजाय बस एक डिजिटल स्ट्रक्चर की जरूरत होगी ।

* सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर, मध्यप्रदेश।

- **लागत में कमी :–** बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु किसी विशेष पर पहुंचने की शर्त खत्म हो जाएगी, इससे ट्रांजेक्शनल (लेन–देन संबंधी) मूल्य के साथ–साथ ट्रांसपोर्ट खर्च में भी कमी आएगी । कैशलेस लेन–देन बढ़ेगा तो रिजर्व बैंक को कम नोट छापने होंगे, जिससे नोटों की छपाई पर आने वाली भारी लागत को कम किया जा सकता है । साथ ही एटीएम को सुचारू रूप से चालू रखने में बैंकों का होने वाला खर्च भी कम होगा ।
    - **जनहितकारी योजनाओं की दक्षता में वृद्धि :–** जनता के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों की दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि पैसे बिचौलियों के हाथ में जाने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा ।[3]

विश्व के विभिन्न देशों के नकदीरहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम

विश्व के कई देशों में वर्षों से नकदी का उपयोग कम हो रहा है और कोविड़–19 महामारी ने इस प्रक्रिया को और गति प्रदान की है । महामारी के दौरान लोगों की नकदी के स्थान पर डिजिटल लेन–देन को प्राथमिकता देना एक मजबूरी हो गई थी (स्वास्थ्य की दृष्टि से) जो कि आगे चलकर स्थाई लेन–देन का माध्यम बन गई । विश्व के कुछ ऐसे राष्ट्र पर दृष्टि डाले, जो कैशलेस सोसाइटी बनने के बहुत करीब हैं ।

- **नार्वे :–** विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक नार्वे यूरोपीय देश है, जो कैशलैस भविष्य के सबसे करीब है। नार्वे के सभी 98 प्रतिशत लोगों के पास डेबिट कार्ड है । 95 प्रतिशत से अधिक आबादी मोबाइल भुगतान एप का उपयोग करती है । नार्वे में दुनिया के सबसे कम भौतिक नकद दरों में से एक है, बिक्री के बिन्दु के केवल 3–5 प्रतिशत लेन–देन का भुगतान नकद द्वारा किया जाता है । 2021 में नार्वे के केन्द्रीय बैंक ने घोषणा की कि वह नकदी मुक्त समाज ने स्विच की सुविधा के लिए डिजिटल मुफ्त विकल्पों की खोज कर रहा था।
- **स्वीडन :–** स्वीडन बैंक नोट जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश था । विडम्बना यह है कि यह उनसे छुटकारा पाने वाले पहले लोगों में से एक है । स्वीडन के कैशलेस समाज के लिए कदम कानून द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और स्वीडन में, एक व्यापारी कानूनी रूप से नकद भुगतान से इंकार कर सकता है । स्वीडन के 98 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास डेबिट कार्ड है। स्वीडन मोबाइल भुगतान के लिए शीर्ष देशों में से एक है ।
- **फिनलैंड :–** बैंक ऑफ फिनलैंड ने भविष्यवाणी की है कि 2029 के अंत तक फिनलैंड पूरी तरह से कैशलैस हो जाएगा । 98 प्रतिशत फिन्स के पास डेबिट कार्ड और 63 प्रतिशत के पास क्रेडिट कार्ड है। फिनलैंड के कैशलेस लेन–देन के 2022 में 60 बिलियन से कम होने की उम्मीद थी। ब्रिक–एंडमोर्टार स्टोर में 80 प्रतिशत फिन्स डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान करना पसंद करते हैं। हालांकि 61 प्रतिशत कैशलैस भविष्य की अवधारणा में विश्वास नहीं करते हैं, 13 प्रतिशत इसके बारे में मिश्रित हैं और केवल 26 प्रतिशत मानते हैं कि पूरी तरह से कैशलेस होना फिनिश समाज के लिए फायदेमंद होगा।
- **हांगकांग :–** हांगकांग की वित्तीय सेवा विकास परिषद के पूर्वानुमान के कारण हांगकांग निकट नकदरहित समाज की ओर बढ़ रहा है । यह भविष्यवाणी करते हुए 2024 तक नकद 1.6 प्रतिशत से अधिक पाइंट–ऑफ सेल लेन–देन नहीं होगा । यह सबसे कम अनुपात होगा । डिजिटल वॉलेट को हांगकांग में सन् 2024 तक शीर्ष स्थान लेने का अनुमान है ।
- **यू.के.** (U.K.) – सॉफ्टवेयर सिफारिश इंजन (Capterra) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार यू.के. को दुनिया के सबसे कैशलेस देशों में माना जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि नकदी कितनी प्रासंगिक है, इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए । फिनटेक प्लेटफार्म एबाउंड के शोध से पता चलता है कि यू.के. के 65 प्रतिशत ग्राहक नियमित रूप से नकदी निकालते हैं और सर्वेक्षण में शामिल 90 प्रतिशत से अधिक

लोगों ने पिछले छह महिनों में एटीएम का इस्तेमाल किया था । केवल लगभग 5 प्रतिशत आबादी पूरी तरह से नकदी मुक्त रह रही है । यू.के. में मर्चेंट मशीन द्वारा शोध करने के लिए, भुगतान इस प्रकार से विभाजित हैं – कार्ड से भुगतान लेन–देन के आधे से अधिक 51 प्रतिशत होते हैं । इसके बाद डिजिटल वॉलेट (32%) द्वारा बनाए गए ।

दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय डिजिट वॉलेट

डिजिटल बटुआ	उपयोगकर्ताओं की संख्या (2022 तक)
अली पे	1.3 अरब
वी चैट पे	900 मिलियन
मोरी वेतन	507 मिलियन
गुगल पे	421 मिलियन
पे पैल	377 मिलियन
च्लजउ	333 मिलियन
चेवदमचम	300 करोड़
सेमसंग पे	140 मिलियन
टमदउव	52 मिलियन
कैश ऐप	36 मिलियन

स्त्रोत : फिनटेक न्यूज।

उद्देश्य

- मन्दसौर जिले में नकदी रहित लेन–देन की स्थिति का विश्लेषण करना ।
- मन्दसौर जिले में नकदी रहित लेन–देन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करना ।

परिकल्पना

- मन्दसौर जिले में पुरूषों के मुकाबले महिला वर्ग डिजिटल लेन–देन कम करता है।
- मन्दसौर जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग डिजिटल लेन–देन कम करते हैं ।
- मन्दसौर जिले में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के लोग डिजिटल लेन–देन कम करते हैं ।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के समंकों पर आधारित है ।

- **द्वितीयक समंक** के लिए पूर्व प्रकाशित शोध पत्र, समाचार पत्र, प्रकाशित पुस्तकों, सरकारी रिपोर्ट (RBI की रिपोर्ट), National Crime Report, एवं विभिन्न वेबसाईट आदि के सहयोग से लिया गया ।
- **प्राथमिक समंक** के संकलन हेतु अध्ययन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए Google Form से कुल 90 लोगों से आंकड़ों का संकलन किया गया है । साथ ही Google Form से जानकारी भरने में असमर्थ लोगों से अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई । ऐसे लोगों की संख्या 35 है । परिकल्पना की जांच के लिए सांख्यिकीय जांच ग^2 का प्रयोग किया गया ।

भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का उपयोग

विमुद्रीकरण के पश्चात् नकदी का उपयोग देश में 83 फीसदी बढ़ा है । हालांकि नकदी आहरण हेतु उपयोग एटीएम में इस दौरान कमी दर्ज की गई। 2016–17 में एटीएम से कैशलेस विड्राल (राशि) नॉमिनल ळक्च का जहां 15.4 प्रतिशत था, वह 2022–23 में घटकर 12.1 प्रतिशत रह गया। विमुद्रीकरण के पश्चात के वर्षों में ळक्च में नकदी के हिस्से का निम्न ग्राफ द्वारा आसानी से समझा जा सकता है ।

विमुद्रीकरण के पश्चात् GDP में नकदी का हिस्सा

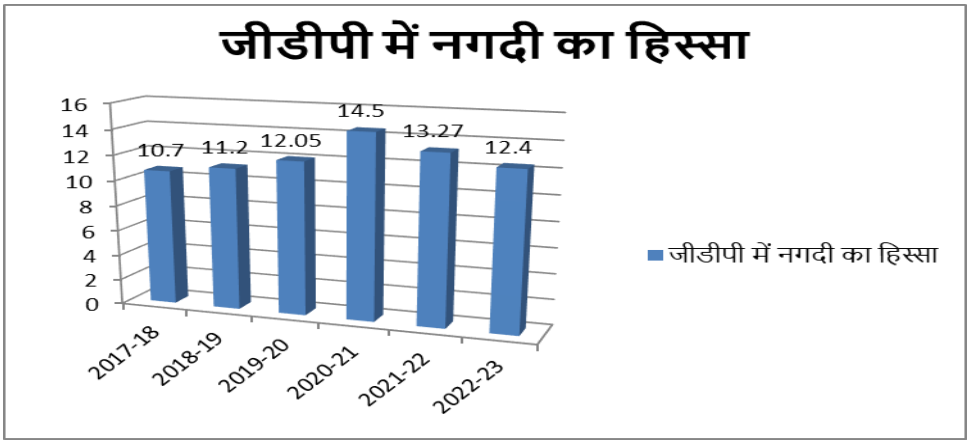

स्त्रोत : दैनिक भास्कर, 28 मई, 2023 अजीत कुमार, वित्त मामलों के विशेषज्ञ के लेख– "रियल एस्टेट, फूड सेक्टर में नकदी का सबसे ज्यादा चलन में")

ग्राफ से स्पष्ट है कि विमुद्रीकरण के पश्चात् लगातार ळक्च में नकदी के हिस्से में वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2020–21 में अधिकतम 14.5 प्रतिशत थी। नोटबंदी से उपजी अनिश्चतता एवं विभिन्न समस्याओं यथा– संक्रमण के कारण यह वृद्धि कही जा सकती है। साथ ही यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि 2020–21 में कोरोना महामारी के चलते लोगों में नकदी रखने की प्रकृति बढ़ी, किन्तु लॉकडाउन के पश्चात् तेजी से बाजार मांग में वृद्धि भी इसका एक बड़ा कारण रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल लेन–देन

भारत में डिजिटल लेन–देन पिछले नौ वर्षों में 100 गुना बढ़ा । वित्त वर्ष 2013–14 में जहां महज 127 करोड़ डिजिटल लेन–देन हुए थे, वहीं यह आंकड़ा 2022–23 में 23 मार्च, 2023 तक बढ़कर 137 करोड़ तक जा पहुंचा है । (स्त्रोत : RBI & E मार्केट एंड रिसर्च)।

एक तरफ पेटीएम, फ्रीचार्ज, पेयू मोबिविक जैसे मोबाइल भुगतान माध्यमों के इस्तेमाल में जबरदस्त तेजी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का प्रयोग बढ़ने से दुकानों, पेट्रोल पम्प व रेस्त्राओं में भी कैश लेस व्यवस्था बढ़ी है ।

पिछले 6 वर्षों में डिजिटल लेन–देन को निम्न ग्राफ द्वारा आसानी से समझा जा सकता है :–

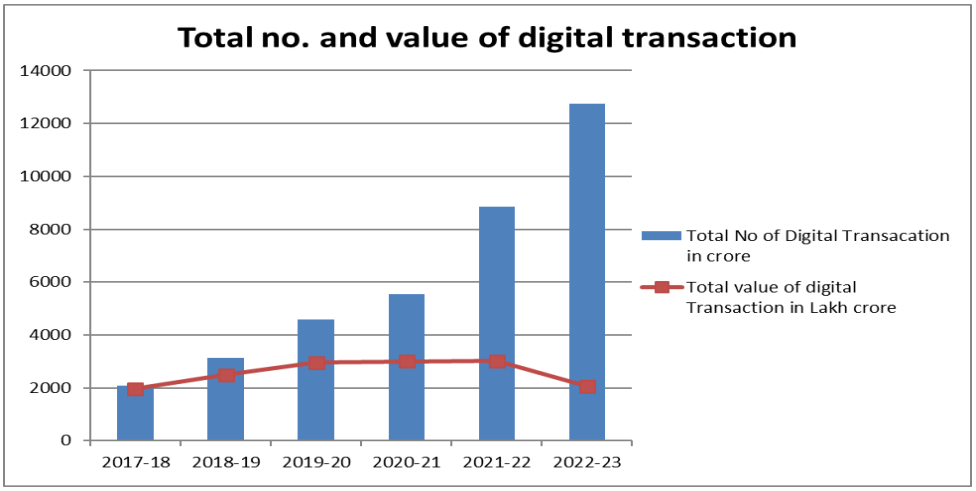

- **नई दिल्ली :** भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था पर गूगल की एक बड़ी रिपोर्ट आई है । गूगल की इस ताजा रिपोर्ट में भारत में तेजी से बढ़ रही इंटरनेट अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सुनहरी तस्वीर की भविष्यवाणी की गई है । गूगल ने यह रिपोर्ट बेन एंड कंपनी के साथ मिलकर तैयार की है ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था साल 2030 तक एक ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर बन जाएगी, जो कि 2010 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होगी।

सबसे तेज बढ़ोतरी e-commerce (ई–कॉमर्स) के क्षेत्र में

इंटरनेट अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी का अनुमान है । सबसे तेज बढ़ोतरी e-commerce (ई–कॉमर्स) के क्षेत्र में होगी । समय के साथ ई–कॉमर्स का हिस्सा सबसे बड़ा हो जाएगा । रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना के लेनदेन में डिजिटल आदतें अपनाने में भारत ने दुनिया के बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है, जिसका सीधा असर डिजिटल लेन–देन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी में देखने में मिल रहा है । अधिकाधिक व्यवसाय या तो सीधे इंटरनेट पर ही आ रहे हैं या जो पारंपरिक रूप से इंटरनेट के बिना चल रहे थे, वो भी डिजिटल हो रहे हैं ।

गूगल की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल बुनियादी ढ़ांचा तेजी से बढ़ रहा है । इसमें ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देने की मौजूदा मोदी सरकार की नीतियों का बड़ा योगदान है।

तेजी से बढ़ रहा है डिजिटल लेन–देन

रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े डिजिटल परिवर्तन के पीछे छोटे शहरों के लोगों की आदतों में आ रहा बदलाव है। भारतीय ग्राहक डिजिटल व्यवहार अपना रहे हैं । बदलते समय के साथ उन्हें सुविधा चाहिए और इसके लिए आने वाले बदलाव को स्वीकार करने में उन्हें हिचक नहीं है । महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ग्राहकों को पर्यावरण का भी ख्याल है ।

प्राथमिक समक विश्लेषण

सारणी : विभिन्न आयु वर्ग में डिजिटल लेन–देन

आयु वर्ग (वर्ष में)	पुरूष			महिला			
	डिजिटल लेन–देन करने वाले हैं	डिजिटल लेन–देन नहीं करने वाले	कुल	डिजिटल लेन–देन करने वाली महिला	डिजिटल लेन–देन नहीं करने वाली	कुल	
< 30	12 (92%)	01 (8%)	13	17 (59%)	12 (41%)	29	42 (34%)
30-45	19 (100%)	-	19	11 (54%)	5 (46%)	16	35 (28%)
45-60	10 (63%)	06 (37%)	16	06 (50%)	6 (50%)	12	28 (22%)
60 >	02 (17%)	09 (15%)	12	02 (25%)	6 (75%)	08	20 (16%)
Total	**51 (85%)**	**09 (15%)**	**60**	**39 (60%)**	**26 (40%)**	**65**	**125**

स्त्रोत : प्राथमिक समंक पर आधारित (कोष्ठक में प्रतिशत को दर्शाया गया है) ।

- सारणी के अनुसार 30–45 वर्ष की आयु वर्ग में 100 प्रतिशत डिजिटल लेन– देन करने वाले पुरूष हैं, जबकि **60** एवं इससे अधिक आयु के पुरूषों में डिजिटल लेन–देन की प्रवृत्ति मात्र 17 प्रतिशत है । महिला वर्ग की बात करें, तो इसमें 30 से कम वर्ष की महिलाओं में डिजिटल लेन–देन की प्रवृत्ति सर्वाधिक 59 प्रतिशत है, जबकि पुरूषों की तरह ही 60 से अधिक वर्ष की आयु की महिलाओं में डिजिटल लेन–देन की प्रवृत्ति सबसे कम 25 प्रतिशत है । यहां हम यह कह सकते हैं कि 60 और 60 वर्ष के अधिक आयु के लोगों द्वारा डिजिटल लेन–देन बहुत कम किया जाता है ।

यहां मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारी परिकल्पना की पुष्टि हमारी प्राथमिक समंक के माध्यम से होती है। जब सर्वे के दौरान इनसे डिजिटल लेन–देन न करने के कारण के विषय में पूछा गया तो अधिकांश ने उपयोग करने में कठिनाई बताई । कुछ ने धोखाधड़ी का डर, तो कुछ ने ऑनलाइन लेन–देन पर अविश्वास जताया ।

सारणी : क्षेत्रानुसार डिजिटल लेन–देन

वर्ग	डिजिटल लेन–देन करने वाले				डिजिटल लेन–देन नहीं करने वाले				कुल योग
	गांव	तहसील	शहर	कुल	गांव	तहसील	शहर	कुल	
महिला	10 (25%)	13 (33%)	17 (42%)	40 (44%)	13 (50%)	07 (27%)	06 (23%)	26 (74%)	66
पुरूष	15 (30%)	16 (32%)	19 (38%)	50 (56%)	04 (44%)	03 (34%)	02 (22%)	09 (26%)	59
कुल	25 (28%)	29 (32%)	36 (40%)	90	15 (43%)	11 (31%)	09 (26%)	35	125

स्त्रोत : प्राथमिक समंक पर आधारित ।

- सारणी के अनुसार गांव में डिजिटल लेन–देन करने वाले कुल 28 प्रतिशत लोग हैं । इसी प्रकार, तहसील में 32 प्रतिशत लोगों द्वारा डिजिटल लेन–देन को अपनाया है, वहीं शहरी लोगों द्वारा डिजिटल लेन–देन करने वाले 40 प्रतिशत है । आंकड़ों से स्पष्ट है कि रिसोर्ट एरिया में डिजिटल लेन–देन आज भी उतना प्रासंगिक नहीं है, जहां नेटवर्क के अभाव में, जानकारी के अभाव में, धोखाधड़ी के डर के कारण एवं स्मार्टफोन नहीं होने के कारण आज भी गांव के 43 प्रतिशत लोग डिजिटल लेन–देन से दूर हैं ।

हमारी परिकल्पना–1 की पुष्टि भी इस सारणी से होती है । हमारे द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 56 प्रतिशत पुरूष वर्ग द्वारा डिजिटल लेन–देन किया जाता है, जबकि 44 प्रतिशत महिला वर्ग द्वारा ही डिजिटल लेन–देन को अपनाया गया है ।

डिजिटल लेन–देन का माध्यम

माध्यम	उपयोग करने वालों की संख्या
UPI/QR Code	70
Net Banking	20
Coral Swip	10
RTGS/NEFT/IMPS	20
सभी का उपयोग	39

सारणी से स्पष्ट है कि सर्वे में प्राप्त जानकारी के अनुसार भी UPI सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला माध्यम है । * NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) के अनुसार जहां मई, 2022 में 323 बैंक UPI से जुड़े हुए थे और 5955.20 लेन–देन द्वारा, कुल 10,41520 करोड़ राशि का लेनदेन UPI के माध्यम से हुआ, जो कि मई, 2023 में बढ़कर 447 बैंकों से कुल 9415.19 लेन–देन द्वारा, कुल 1489145.50 करोड़ की राशि का लेन–देन किया गया। (स्त्रोत : NPCI- National Payment Corporation of India, Website- httpsi//www.npci.org.in)

- सर्वे में कुल 20 लोगों द्वारा ही RTGS/NEFT/IMPS का इस्तेमाल किया । वहीं 39 लोगों द्वारा सभी माध्यमों से डिजिटल लेन–देन को स्वीकार किया गया ।

सर्वे के अनुसार, 90 में से कुल 40 लोग कोविड के पहले और विमुद्रीकरण के समय से डिजिटल लेन–देन कर रहे थे, जबकि 50 लोगों ने कोविड महामारी के समय डिजिटल लेन–देन मजबूरी में करना सीखा, जो कि निरंतर जारी है ।

सर्वे में कुल 35 लोगों के द्वारा डिजिटल लेन–देन न करना स्वीकार किया गया, जब उनसे इसका कारण जानना चाहा तो उनके द्वारा निम्न कारण बताए गए :–

डिजिटल लेन–देन न करने का कारण का विश्लेषण

डिजिटल लेन–देन न करने का कारण	**संख्या**
धोखाधड़ी का डर	05
डिजिटल लेन–देन करना नहीं आता	10
ऑनलाइन लेन–देन पर विश्वास नहीं	11
स्मार्टफोन नहीं है	09′

(′इसमें 06 महिलाएं और 03 पुरूष)

- सर्वे में केवल 05 लोगों द्वारा डिजिटल लेन–देन के समय धोखे की जानकारी दी गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश एवं भारत में कुल साइबर क्राइम की स्थिति इस प्रकार है :–

	Froud ATM	**Online Banking Froud**	**OTP Froud**	**Others**	**Cheating Sec.420**
मध्यप्रदेश	12	48	09	18	30
भारत	1899	4823	2028	3633	6342

स्त्रोत : NCRB

हालांकि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों के साथ धोखा होता है, उनके द्वारा जानकारी के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । हमने सर्वे में जानना चाहा कि डिजिटल लेन–देन के दौरान होने वाले धोखे के बाद की जाने वाली कार्यवाही के बारे में तो कुल 90 लोग, जो डिजिटल लेन–देन करते हैं, उनमें से 59 लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी ।

- डिजिटल लेन–देन सहजता के सवाल पर कुल 90 में से 70 लोगों ने सरल बताया, जबकि 20 लोगों ने बताया कि पहले थोड़ा मुश्किल लगता था, पर अब करते–करते आदत हो गई है ।
- डिजिटल लेन–देन से हुए आसान कार्य की बात पर लगभग सभी 110 लोगों ने सहमति व्यक्त की । यहां तक कि जो डिजिटल लेन–देन नहीं करते हैं, वे भी यह मानते हैं कि इससे कार्य बहुत आसान हो गए हैं, केवल 15 लोगों ने यह माना कि कार्य आसान नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ के पास स्मार्ट फोन नहीं है और उन्हें उसका उपयोग करना भी नहीं आता है ।

परिकल्पना की जांच – X^2 ज्मेज द्वारा

परिकल्पना–1 : मन्दसौर जिले में पुरूषों के मुकाबले महिला वर्ग डिजिटल लेन–देन कम करता है ।

	डिजिटल लेन–देन करते हैं	**डिजिटल लेन–देन नहीं करते हैं**	**योग**
पुरूष	50	09	59
महिला	40	26	66
कुल	**90**	**35**	**125**

शून्य परिकल्पना डिजिटल लेन–देन की आदत एवं लिंग दोनों स्वतंत्र है।

अवलोकित आवृत्ति (F_0)

50	09	59
40	26	66
90	35	125

प्रत्याशित आवृत्ति (F_e)

$\frac{59x90}{125} = 43$	$\frac{59x35}{125} = 17$	59
$\frac{90x66}{125} = 47$	$\frac{35x66}{125} = 18$	66
90	35	125

X^2 की गणना

f_0	f_e	$f_0 - f_e$	$(f_0 - f_e)^2$	$(f_0 - f_0)^2/f_e$
50	43	7	049	1.139
09	17	-8	64	3.765
40	47	-7	-49	1.042
26	18	8	64	3.556
				$X^2 = 9.502$

d.f. = (c-1) (r-1)

(2-1) (2-1)

d.f. = 1

व्याख्या :– 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 1 कण्णि के लिए सारणी मूल्य 3.84 है, जबकि परिगणित मूल्य 9.502 है, जो कि सारणी मूल्य से अधिक है । अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लिंग और डिजिटल लेन–देन स्वतंत्र नहीं है। वस्तुतः लिंग और डिजिटल लेन–देन का आपसी सम्बन्ध है ।

परिकल्पना –2

मन्दसौर जिले में गांव की तुलना में शहरी क्षेत्र में डिजिटल लेन–देन अधिक किया जाता है ।

	डिजिटल लेन–देन करने वाले	**डिजिटल लेन–देन नहीं करने वाले**	**योग**
गंव	25	15	44
त्हसील	29	11	36
शहर	36	09	45
योग	**90**	**35**	**125**

अवलोकित आवृत्ति (F_0)

25	15	44
29	11	36
36	09	45
90	35	128

प्रत्याशित आवृत्ति (Fe)

$\frac{44x90}{125} = 32$	$\frac{44x35}{125} = 12$	44
$\frac{36x90}{125} = 26$	$\frac{36x35}{125} = 10$	36
$\frac{90x45}{125} = 32$	$\frac{35x45}{125} = 13$	45
90	35	125

X^2 की गणना

f_0	f_e	$f_0 - f_e$	$(f_0 - f_e)^2$	$(f_0 - f_0)^2/f_e$
25	32	-7	49	5.444
29	26	3	9	0.3462
36	32	4	16	0.5000
15	12	3	9	0.7500
11	10	1	1	0.1000
9	13	-4	16	1.230
				8.3702

d.f. = (c-1) (r-1)

(2-1) (3-1)

1x2 = 2

d.f. 2 के लिए सारणी मूल्य 8.3702 Tablevalue < calculated value। हमारी परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है कि मन्दसौर जिले शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन–देन की प्रवृति अधिक है ।

डिजिटल लेन–देन में सावधानियां

- कार्ड खो जाने या चुरा लिये जाने पर तत्काल कस्टमर केयर द्वारा कार्ड ब्लॉक करवा देना चाहिए ।
- फिशिंग, कई बार बैंकों के नाम से जांच के नाम पर ई–मेल, फोन कॉल्स आते हैं । इस पर अपनी गुप्त जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए ।
- वायरस, स्पाईवेयर की लॉगिंग, हमारे कम्प्यूटर या वाईफाई नेटवर्किंग में कुछ जासूसी वायरस हमारी गतिविधि पर नजर रख सकते हैं एवं हमारी ऑनलाइन भुगतान की जानकारी को अपने कंट्रोलर तक पहुंचा सकते हैं । इसके लिए कम्प्यूटर वायरस सुरक्षा व सिस्टम अपडेट करते रहे ।
- स्किमिंग, कई कारोबारी ठिकानों में धोखेबाज कर्मचारी छोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा हमारे क्रेडिट कार्ड की चुंबकीय पट्टी की जानकारी चुरा लेते हैं । इसलिये सावधानीपूर्वक लेन–देन के समय अपने कार्ड पर नजर रखनी चाहिए ।
- आइडेंटटी थेफ्ट (पहचान की चोरी) कुछ धोखेबाज हमारे नाम पर डाक का पता बदलने का आग्रह बैंक से कर देते हैं । फिर कार्ड खो जाने की शिकायत कर नया कार्ड इश्यू करवा लेते हैं । अतः अपने होम बैंक व बैंक खातों पर नजर रखनी चाहिए ।
- बैंक से डेटा चोरी, कई बार बैंक के कम्प्यूटर व सर्वर से ही डेटा चोरी हो जाते हैं । इससे बचने के लिये बैंकों को मजबूत सुरक्षा फीचर्स/तंत्र के साथ–साथ अपने बैंक कर्मचारियों की संदेहास्पद गतिविधियों के प्रति भी सतर्क रहना चाहिये ।
- वेबसाइट्स पर ीजजचेरूध्ध् वाले यूआरएल. का प्रयोग करें, ीजजचरूध्ध्का नहीं । ऐसे वेबसाइट्स के वेब पते के आगे ताले का चित्र दिखाई देता है ।
- ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिये यदि संभव हो तो वेरीफाई वीजा, मास्टर कार्ड, सिक्योर कोड, नेट सेफ जैसे उपायों को वरीयता दें ।
- यदि क्रेडिट कार्ड पर बीमा सुविधा हो तो ले लें, लॉग इनके बाद लॉग आउट अवश्य करें ।
- मुफ्त या ट्रायल वर्जन के स्थान पर एक अच्छी एंटी–वायरस, एंटी–स्पाईवेयर, फिशिंग अलर्ट व टोटल सिक्योरिटी का प्रयोग करें ।
- दुरूपयोग की स्थिति में तुरंत साइबर क्राइम शाखा, अपने बैंक व अपने बीमाकर्ता को इसकी जानकारी दें ।

सुझाव

- असंगठित क्षेत्र की बैंकिंग नेट तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नेटबैंकिंग की समस्या का पुख्ता हल निकाला जाना चाहिए ।
- डिजिटल लेन–देन को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता एवं जानकारी प्रसारित की जानी चाहिए ।
- डिजिटल लेन–देन के लाभ प्रसारित किए जाने चाहिए ।
- प्रत्येक व्यक्ति तक स्मार्ट फोन की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए ।
- हमें अपने साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना होगा ।
- ऑनलाइन लेन–देन में अतिरिक्त शुल्क नहीं होने चाहिए ।
- डिजिटल लेन–देन के दौरान होने वाले धोखे पर की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी को प्रचारित एवं प्रसारित किया जाना चाहिए ।

निष्कर्ष

यह सत्य है कि जितनी सुविधा उतनी दुविधा, किन्तु सावधानी में ही तो सुरक्षा है । जब विश्व के अधिकांश देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम उस पुरानी पटरी पर नहीं चल सकते । यदि समस्याएं हैं, असुरक्षा का डर है, तो कुशल तकनीक के प्रयोग का इस्तेमाल कर लोगों में जागरूकता व सतर्कता फैलाकर इसे सफल बनाया भी तो जा सकता है । जिस गति से भारत में डिजिटल लेन–देन का उपयोग बढ़ रहा है, यह कहना गलत नहीं होगा कि 2030 तक भारत भी कैशलेस अर्थव्यवस्था के करीब होगा । जरूरत है तो सावधानीपूर्ण और बिना लालच के सही तरीके से उपयोग की ।

सन्दर्भ गन्थ सूची

1. मेकिन्स ग्लोबल रिपोर्ट
2. फिनटेक –न्यूज
3. अजित कुमार, "रियल एस्टेट फुड सेंटर में नकदी का सबसे ज्यादा चलन", दैनिक भास्कर, 28 मई, 2023
4. RBI – मार्केट एंड रिसर्च
5. NPCI- National Payment Corporation of India,
6. https://www.npci.org.in
7. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट – 2021
8. https://www.drishtiias.com/hindi/paper3/cyber-securityincashless-economy/print/manul
9. पी.एस.यू. वॉच हिन्दी, च्नइसपैमक वद 13 श्रनदमए 2023 10.24 pm
10. Ms. Saruka Kalgutkar "Cashless Economy in India Present Scenaria"
11. Inspira- JournL Commerce Factor : 5.660, Valuue 08, No. 01, Jan- March, 2022, pp-124-128
12. https://www.meity.gov.in/digidhan
13. https://dbie.rbi.org.in/

❖◆❖